डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 दिसम्बर, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 दिसम्बर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 13 | भोपाल | 1 दिसम्बर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

डेयरी विकास के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पशु चिकित्सा सेवाओं का किया जाए विस्तार

1000 नई समितियां बनीं, 585 समितियों को बनाया गया गतिशील

700 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग की समीक्षा की

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के कार्य निरंतर संचालित किए जाएं। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना चाहिए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग सभी कार्य सुनिश्चित करें। गत दो वर्ष में डेयरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी अर्जित हुई हैं। इन्हें निरंतर कायम रखा जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में एक वर्ष में करीब 1000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं। साथ ही 585 निष्क्रिय समितियों को गतिशील बनाया गया है।

पशु चिकित्सा कार्य को दें प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशु चिकित्सा एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसकी अवहेलना नहीं होना चाहिए। पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। राज्य के पशुधन के मान से चिकित्सक और सेवा भावी स्टॉफ की व्यवस्था से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत पशु चिकित्सालयों और पशु औषधालयों की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि प्रदेश में 1065 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं।

700 पदों पर नियुक्ति शीघ्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि लोकसेवा आयोग द्वारा शीघ्र ही 200 पशु चिकित्सकों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। इसी तरह कर्मचारी चयन मंडल ने 500 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पदों की पूर्ति के लिए परिणाम घोषित किए हैं। इनकी पदस्थापना भी शीघ्र हो जाएगी। आगामी वर्ष 735 पशु चिकित्सालय स्थापित करने की प्रक्रिया भी संचालित है। बताया गया कि प्रदेश में गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए राशि दी जा रही है। प्रदेश में दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों से खरीदे गए दूध पर प्रति लीटर ढाई रुपए से लेकर साढ़े आठ रुपए तक वृद्धि की गई है। दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य के नियमित और समय पर भुगतान के लिए समय- सीमा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि गाय के दूध से निर्मित घी, गौ काष्ठ और गौ मूत्र जैसे पदार्थों के विक्रय की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए।

सहकार्यता अनुबंध के बाद बनी मैनेजमेंट कमेटी

बैठक में जानकारी दी गई कि गत 13 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश शासन, एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, संबंद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच सहकार्यता अनुबंध हुआ है। इसके परिपालन में दुग्ध संघों में मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी में डेयरी डेवलपमेंट प्लान शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्यप्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है। इसी तरह पशुपालन से जुड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के कार्य में भी मध्यप्रदेश देश में तृतीय स्थान पर है।

बैठक में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के दायित्वों, आर्चा विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, टीकाकरण कार्य, हिरण्यगर्भा अभियान, दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान, क्षीर धारा ग्राम योजना स्वावलंबी योजना और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता पुरस्कार योजना के संबंध में चर्चा हुई।

पैक्स एवं स्व-सहायता समूह साझेदारी से खुलेगा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय

मंत्री श्री सारंग ने ली सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीपीपीपी अंतर्गत जीआईएस-2025 के दौरान हुए एमओयू की प्रगति, नवाचार प्रकोष्ठ की गतिविधियों तथा सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स और स्व-सहायता समूहों के बीच सहयोगात्मक ढांचा तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े अवसर विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि पैक्स–स्व सहायता समूह के बीच साझेदारी का स्पष्ट एवं क्रियाशील रोडमैप तैयार किया जाए। जिससे ग्रामीण स्तर पर नए रोजगार व उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता ही वह सशक्त नेटवर्क है जो हर घर तक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को पहुँचा सकता है। हमें स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को पहचानकर योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि CPPP (Co-operative Public Private Partnership) नवाचार की सक्सेस स्टोरी तैयार की जाए। इस नवाचार को दस्तावेज़ रूप में भी संकलित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिला स्तर पर सहकारी बैंकों के सीईओ के माध्यम से किसानों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव एकत्र किए जाएं। जिससे मुख्यालय से आवश्यक सुधार करते हुए योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन किया जा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (उपभोक्ता संघ) श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक (बीज संघ) श्री महेंद्र दीक्षित, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित किया

श्री अमित शाह ने कहा कि NCDC सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एक मजबूत माध्यम बन कर उभरी है

सहकारिता मंत्री श्री शाह ने चीनी मिलें व डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा

श्री शाह ने कहा कि देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा को जमीन पर उतारने में NCDC की महत्त्वपूर्ण भूमिका; इससे ड्राइवरों को होगा बड़ा फायदा

पिछले कुछ वर्षों में NCDC द्वारा सहकारी संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता लगभग 4 गुना बढ़कर रु. 95,200 करोड़ पहुंची

NCDC की मदद से 1,070 FFPOs का सुदृढ़ीकरण, 2,348 पर काम जारी

श्री शाह ने डेयरी, पशुधन, मत्स्य व महिला सहकारी समितियों पर विशेष ध्यान देने को कहा: NCDC द्वारा किया जायेगा रु. 20,000 करोड़ का आवंटन

NCDC दे रहा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दिए गए ट्रॉलरों से महिलाएं हुई आर्थिक रूप से मजबूत

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में नए कार्यालय खोलकर NCDC ने बढ़ाया नेटवर्क

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और एनसीडीसी इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। श्री शाह ने बताया कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मत्स्यपालकों, छोटे उत्पादकों तथा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सहकारिता देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एनसीडीसी का कुल संवितरण वित्त वर्ष 2020-21 के 24,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। पिछले चार वर्षों में एनसीडीसी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वित्तीय समावेशन, नवाचार तथा विस्तार के नए आयाम स्थापित किए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी औरआजीविका सुनिश्चित करता है। बीते चार वर्षों में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, शुद्ध एनपीए शून्य रखा है और 807 करोड़ रुपये का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जिससे संस्था की विश्वसनीयता और साख मजबूत हुई है। एनसीडीसी ने डीसीसीबी, स्टेट कोआपरेटिव बैंकों और स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा एवं विपणन के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया है।

किसान उत्पादक संगठन के रूप में पैक्स के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह सुनिश्चित हो रहा है कि किसानों को उनकी उपज पर उचित लाभ मिले तथा व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामुदायिक लाभ को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हरित क्रांति के बाद जैविक खेती, ऑर्गेनिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) जैसी बहु-राज्य सहकारी संस्थाएँ प्रतिबद्ध हैं।

मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी ने 1,070 एफएफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया है तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 2,348 एफएफपीओ को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु ट्रॉलर खरीदने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य समुदाय, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।

श्री अमित शाह ने कहा कि चीनी व डेयरी के क्षेत्र में अधिक लाभ के लिए सर्कुलर इकॉनमी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान के आधार पर एनसीडीसी ने 56 चीनी मिलों को इथेनॉल संयंत्र, को-जेन और कार्यशील पूंजी के लिए 10,005 करोड़ रुपये का संवितरण किया है, जिससे मिलों को वैकल्पिक आय स्रोत और कम दर पर ऋण प्राप्त हुआ है।

श्री अमित शाह ने बताया कि एनसीडीसी सहकारिता आधारित "भारत टैक्सी" राइड-हेलिंग सेवा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, नई बहु-राज्य सहकारी समिति का पंजीकरण हो चुका है और ड्राइवर सदस्यता तथा तकनीकी विकास जारी है।

एनसीडीसी ने विजयवाड़ा में नया क्षेत्रीय कार्यालय तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उप-कार्यालय स्थापित कर सहकारिता को दूरस्थ स्थानों तक पहुँचाया है।

31 जुलाई 2025 को स्वीकृत 2,000 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के आधार पर एनसीडीसी 20,000 करोड़ रुपये जुटाकर डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कृषि और महिला सहकारी समितियों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही NCDC ने शहरी सहकारी बैंकों के अंब्रेला संगठन और सहकार सारथी में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को प्रोद्योगिकी सेवाएं प्रदान की जाएँगी।

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीडीसी का "कोऑपरेटिव इंटर्न" कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है, जिसके अंतर्गत चयनित प्रशिक्षु सहकारी संस्थाओं को तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

एनसीडीसी की महापरिषद में 51 सदस्य शामिल रहे, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शीर्ष सहकारी समितियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह परिषद सहकारी विकास, कृषि, ग्रामीण अवसंरचना और संबद्ध क्षेत्रों में वित्तपोषण हेतु नीतियाँ व दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाला सर्वोच्च निकाय है।

हकीमाबाद PACS में 72वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम आयोजित

सीहोर। जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर के तत्वाधान में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह–2025 के अंतर्गत दिनांक15 नवम्बर 2025को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हकीमाबाद में सहकारिता विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम क मुख्य अतिथि वरिष्ठ सहकारी नेता माननीय देवीसिंह परमार 'काकाजी' (पूर्व अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; संचालक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सीहोर) रहे।

कार्यक्रम में रामचन्द्र परमार (सरपंच, बगड़ावदा), मांगीलाल चौहान (सरपंच, हकीमाबाद), दिलीप सिंह मेवाड़ा, दयाराम पाटीदार, मनोहर सिंह ठाकुर तथा मोहनसिंह परमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

त्रिभुवनदास सहकारी यूनिवर्सिटी : सहकारिता शिक्षा का नया अध्याय

मुख्य अतिथि माननीय देवीसिंह परमार 'काकाजी' ने अपने संबोधन में बताया कि देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त एवं व्यापक बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में अनेक अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में "जन-जन के सहकारी नेता" तथा सहकारिता क्षेत्र में आजीवन समर्पित रहे त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर गुजरात में भारत की प्रथम त्रिभुवनदास सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र हेतु डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. जैसी डिग्रियों की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे युवा वर्ग सहकारिता को एक नए करियर एवं व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी आंदोलन के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का महत्त्वपूर्ण केंद्र बनेगी।

मध्यप्रदेश बना भारत का फूड-बास्केट, कृषि विकास में रचा नया इतिहास

भोपाल :कभी 'बीमारू राज्य' और विकास की दौड़ में पिछड़ा माना जाने वाला मध्यप्रदेश आज आत्मनिर्भरता, कृषि समृद्धि और तीव्र आर्थिक विकास का प्रतीक बन चुका है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व, सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और किसानों की अटूट मेहनत का परिणाम है। मध्यप्रदेश अब न केवल विकास दर में अग्रणी है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में नई पहचान बना चुका है। यही कारण है कि भारत का हृदय प्रदेश अब देश का नया 'फूड-बास्केट' कहलाने लगा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि मध्यप्रदेश ने कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में जो आशातीत प्रगति की है, उसमें हमारे अन्नदाताओं की महती भूमिका है। बीते वर्षों में मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन, सिंचाई विस्तार और किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर देश का नया 'फूड बास्केट' बनने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य की विकास दर अब डबल डिजिट में पहुंच चुकी है, जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का संकल्प लिया है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, पर्याप्त बिजली आपूर्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, भावांतर भुगतान योजना और कृषि यंत्रीकरण ने किसानों से जीवन में खुशहाली आ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आज मध्यप्रदेश गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन और तिलहन उत्पादन में देश में अग्रणी बन चुका है। पंजाब और हरियाणा जैसे परम्परागत कृषि सम्पन्न राज्यों को कई फसलों के उत्पादन में पीछे छोड़ना राज्य के किसानों की मेहनत और सरकार की संवेदनशील नीतियों का ही परिणाम है। हमने कृषि के साथ-साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में भी राज्य ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज चेन जैसे अनेक कदम किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है - हर खेत तक पानी, हर किसान तक प्रगति और हर घर तक समृद्धि। मध्यप्रदेश का किसान अब सिर्फ़ अन्नदाता नहीं, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का निर्माणकर्ता बन चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और राज्य के पूरे कृषि अमले को इस राष्ट्रीय उपलब्धि की ओर बढ़ने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा को सशक्त करेगा, बल्कि

वैश्विक कृषि मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

कृषि समृद्ध प्रदेश बनने की कहानी

कभी सीमित सिंचाई साधनों, अस्थिर बिजली आपूर्ति और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही थी। किसानों की आमदनी सीमित थी और ग्रामीण जीवन में भी कुछ कठिनाइयां थीं। परंतु बीते दो दशकों में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को अपनी नीतियों के केंद्र में रखकर जो कार्य किया, उसने राज्य की तस्वीर ही बदल दी। हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश ने 24 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय विकास औसत से कहीं अधिक है। यह प्रगति बताती है कि मध्यप्रदेश अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कृषि विकास में आई नई क्रांति

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कृषि क्षेत्र में देखा गया है। बीते वर्षों में राज्य सरकार ने कृषि को सिर्फ़ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प लिया। किसानों को फसल उत्पादन की लागत में राहत देने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। कृषक कल्याण मिशन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी जतन किए जा रहे हैं। भावांतर भुगतान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फ़सल खरीदी और इस खरीदी पर बोनस राशि भी देने जैसे प्रयासों ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा उन्नत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों ने भी खेती-किसानी को और अधिक रूचिकर, उत्पादक और टिकाऊ बनाया है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का खेत तक विस्तार भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को आपस में जोड़ने और केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक जैसी परियोजनाओं से लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण से रबी सीजन में फसलों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई है।

खेती-किसानी की बदलती परिभाषा

मध्यप्रदेश के किसान अब पारम्परिक खेती तक सीमित नहीं हैं। वे नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार ला रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मल्टीक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों ने कृषि को एक व्यावसायिक रूप दिया है। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों की सक्रिय भूमिका ने किसानों को नवीनतम जानकारी सहित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया है। अब किसान बाजार की मांग के अनुसार फसलें पैदा कर रहे हैं और निर्यात की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में नया इतिहास

आज मध्यप्रदेश गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य के कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, बीते वर्षों में प्रदेश का अनाज उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। गेहूं उत्पादन में मध्यप्रदेश अब देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बन चुका है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही स्तरों पर राज्य ने पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दलहन और तिलहन उत्पादन जैसे चना, मसूर और सोयाबीन की पैदावार ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मध्यप्रदेश अब देश के कुल चना उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है।

धान उत्पादन

धान की फसल उत्पादन मामले में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। बालाघाट, बैतूल, मंडला, सिवनी और डिंडोरी जैसे जिले अब धान की नई मंडियां बन गए हैं। यहीं से देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है।

किसानों की समृद्धि से ग्रामीण विकास

कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में आमूलचूल प्रगति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। गांवों में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं, कृषि-आधारित उद्योगों का विकास हुआ है और युवाओं में खेती को लेकर नया उत्साह पैदा हुआ है। जहां पहले खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी, वहीं आज यह आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। कृषि उपज मंडियों का डिजिटलीकरण, e-NAM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री की सुविधा और मूल्य पारदर्शिता ने किसानों को बाजार की बेहतर समझ विकसित कर समुचित कीमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

कृषि से औद्योगिक विकास तक

मध्यप्रदेश की तेज कृषि विकास दर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश कृषि आधारित उद्योगों और एग्रो प्रोसेसिंग का केंद्र बनने जा रहा है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक हब के निर्माण से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ेगी। सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट 'वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना भी इस दिशा में मददगार सिद्ध हो रही है। यह किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तो कारगर है ही, ग्रामीण रोजगार को भी यह योजना स्थायी बना रही है।

नया मध्यप्रदेश, नया आत्मविश्वास

मध्यप्रदेश आज बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब यह राज्य विकास के नए अध्याय लिख रहा है। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, फ़ार्म टू लैब हर जगह परिवर्तन की एक नई लहर महसूस की जा रही है। प्रदेश के किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहे, बल्कि "राष्ट्रनिर्माता"औरऊर्जादाता भी बन रहे हैं। किसानों को उनके खेत में सोलर पम्प लगाने के लिये अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। किसानों के परिश्रम और सरकार की किसान हितैषी संवेदनशील नीतियों ने मध्यप्रदेश को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिसकी कल्पना भी कभी दूर की कौड़ी लगती थी।

औषधीय फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य मध्यप्रदेश

46 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होती ईसबगोल, अश्वगंधा की खेती

भोपाल :मध्यप्रदेश औषधीय फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 46 हजार 837 हैक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों ईसबगोल, सफेद मूसली, कोलियस व अन्य फसलों की खेती की जा रही है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग सवा लाख मीट्रकि टन औषधीय फसलों का उत्पादन हुआ है। देश और विदेश में औषधीय फसलों की बढ़ती मांग के कारण किसानों का भी आकर्षण इन फसलों के उत्पादन की ओर बढ़ा है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 44 हजार 324 हैक्टेयर में औषधीय फसलों की बोनी की गई थी । जो 2024-25 में बढ़कर 46 हजार 837 हैक्टेयर हो गया यानिकी 2 हजार 512 हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। इन फसलों का वर्ष 2021-22 में उत्पादन एक लाख 16 हजार 848 मीट्रिक टन था जो 2024-25 में बढ़कर एक लाख 24 हजार 199 मीट्रिक टन हो गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत में औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश की सर्वाधिक भागीदारी है। एक अनुमान के अनुसार देश में औषधीय फसलों का 44 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में उत्पादित होता है। राज्य सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन दे रही है। औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करती है। सरकार पारंपरिक फसलों के अलावा औषधीय पौधों जैसी वाणिज्यिक फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल सके। औषधीय पौधों की खेती और संग्रह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में प्रमुख फसलें अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, तुलसी और कोलियस जैसी कई औषधीय फसलों का उत्पादन होता है। प्रदेश में 13 हजार हैक्टेयर में ईसवगोल, 6 हजार 626 हैक्टेयर अश्वगंधा, 2 हजार 403 हैक्टेयर में सफेद मूसली, 974 हैक्टेयर में कोलियस तथा 23 हजार 831 हैक्टेयर में अन्य औषधी फसल की बोनी की गई है। मध्यप्रदेश सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का औषधीय पौधों की खेती आकर्षित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा डाबर, वैद्यनाथ जैसी आयुर्वेद कम्पनियों, संजीवनी क्लिनिक में विंध्यवैली जैसे ब्रांड के माध्यम से औषधीय उत्पादन को बाजार मुहैया करा रही है।

नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित गुना में 72वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का हुआ समापन

गुना :अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एवं 72वॉ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम के तत्वाधान मे गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित गुना स्थान सम्राट होटल गुना में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें भाजपा जिलाध्य क्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, उप आयुक्त सहकारिता श्री मुकेश कुमार जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकार, सीसीबी गुना श्री कमल मकाश्रे, कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अमित सौगानी, अध्यक्ष, गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित गुना द्वारा की गई।

कार्यक्रम का प्रारंभ वन्दे मातरम राष्ट्रीय गीत, एवं सहकारी गीत के गायन से किया गया। कार्यक्रम मे गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित गुना का 25 वर्ष का सफर एवं बैंक की सफलता पर प्रिजेटेंशन के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया है।

कार्यक्रम में बैक द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधाऐं, एफडी अधिकतम ब्याज, एटीएम कार्ड, एनईएफटी, एवं जिले मे नई शाखा खोलने पर अध्यक्ष द्वारा सभी अवगत कराया। गौरान्वित कार्यक्रम के साथ 72वॉ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 एवं 72वॉ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 14 नवम्बर से 20 नवम्बर 2025 में चलाये गये सहकारी प्रचार-प्रसार वाहन गुना, एवं अशोकनगर जिले मे भ्रमण करते हुये नवाचार, सोसायटी को आत्मनिर्भर, डिजीटलीकरण, मॉडल पैक्स, दुग्ध, मत्स्य समितियों की नवीन वायॅलाज, सहकार से समृद्धि पहल एवं योजनाओ का प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम मे श्री नवीन शर्मा बरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, श्री शिवम् सिंघल सहकारी निरीक्षक/प्रशासक, जिला सहकारी संघ मर्यादित गुना, श्री सत्येन्द्र शर्मा प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित गुना, सहकारिता विभाग गुना के अधिकारी/कर्मचारीगण, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित गुना के संचालकगण, सदस्य एवं अधिकारी/कर्मचारी, तथा सीसीबी गुना की अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान भाई-बहनों को एक और बड़ी सौगात

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को 'स्थानीयकृत जोखिम' के रूप में मान्यता; धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया

तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभ

किसान सुरक्षा को मजबूत करने हेतु PMFBY के तहत नई प्रक्रियाओं की घोषणा - PMFBY को अधिक समावेशी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

खरीफ 2026 से लागू होंगी नई प्रक्रियाएँ

नई दिल्ली | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान भाई-बहनों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें 'ऐड-ऑन कवर' के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी।

यह निर्णय विभिन्न राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और किसानों को अचानक, स्थानीयकृत और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रक्रियाएँ PMFBY परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाई गई हैं, और खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू की जाएँगी।

देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। दूसरी ओर, तटीय एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसानों को वर्षा और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण समान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता रहा है। वर्ष 2018 में इस जोखिम को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी से हटाए जाने से किसानों के लिए एक बड़ा संरक्षण अंतर उत्पन्न हो गया था।

इन उभरती चुनौतियों को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को PMFBY के तहत समयबद्ध और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान जलभराव दोनों को शामिल किए जाने से PMFBY और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और किसान हितैषी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

72वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह: ट्रांसपोर्ट सहकारी बैंक में सहकारिता कार्यक्रम

भोपाल। 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सहकारी बैंक में सहकारिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारी ध्वज फहराने और सहकारिता गीत से हुई।अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपने उद्बोधन में बैंक की उपलब्धियों, सदस्य उन्नयन, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तथा परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष ऋण सुविधाओं पर प्रकाश डाला। वित्तीय साक्षरता सत्र में सुरक्षित ऋण उपयोग, डिजिटल लेनदेन और सहकारी सिद्धांतों की जानकारी दी गई।

72वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह ● भोपाल में सहकारिता के सतरंगे उत्सव का शानदार शुभारंभ

“सहकारिता से आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह (14–20 नवम्बर 2025) का शुभारंभ सहकारी भावनाओं से ओत-प्रोत वातावरण में हुआ। संघ मुख्यालय का परिसर सहकारिता के, सतरंगे ध्वजों, नारों और सामूहिकता की भावना से गूँजता रहा।

ध्वजारोहण: सहकारिता के सम्मान का गौरवपूर्ण क्षण

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा सहकारी ध्वज फहराकर हुआ। इस अवसर पर—

- महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह
- संघ मुख्यालय के अधिकारी–कर्मचारी
- सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल के अधिकारी–कर्मचारी
- प्रशिक्षणरत प्रतिभागी
- CHCDS परियोजना की महिला प्रशिक्षार्थी
- कॉलेजों के छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के साथ ही परिसर में सहकारिता के जयघोष गूँज उठे और वातावरण समरसता, उत्साह तथा गर्व से भर गया।

“हम” की भावना को जीवन का आधार बनाएं

प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने अपने प्रभावी, प्रेरक और विचारोत्तेजक उद्बोधन में कहा कि सहकारिता भारतीय समाज की प्राचीन सामूहिकता-आधारित परंपरा है। उन्होंने कहा— “सहकारिता केवल संस्था नहीं, यह ‘हम’ की ऐसी जीवनदृष्टि है जो हमें जोड़ती है, उन्नति की ओर ले जाती है और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी विकास का समान अवसर प्रदान करती है।” उन्होंने आगे कहा कि— “भारत की आत्मनिर्भरता का मार्ग सहकारी संगठनों की मजबूती से होकर गुजरता है। यदि हम ‘मैं’ से आगे बढ़कर ‘हम’ बन जाएँ, तो गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और आर्थिक कमजोरियाँ स्वतः समाप्त होने लगेंगी। सहकारिता वह शक्ति है, जिसके सहारे एक-एक किसान, महिला समूह और युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।”उन्होंने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा—“युवा यदि सहकारी तंत्र को समझें, अपनाएँ और अपनी ऊर्जा इसमें लगाएँ, तो आने वाला भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि विश्व में सहकारिता का सबसे सशक्त मॉडल प्रस्तुत करेगा।”

उन्होंने सभी कर्मचारियों को पारदर्शिता, अनुशासन, संवेदनशीलता और सामूहिकता को अपने कार्य का मूल सिद्धांत बनाने की प्रेरणा दी।

सहकारी रैली: जन-जागरूकता का उत्सव

ध्वजारोहण के बाद त्रिलंगा और शाहपुरा क्षेत्रों में एक सहकारी रैली निकाली गई। इसमें—

- प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन
- महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह
- अधिकारी–कर्मचारी
- महिला स्वयं सहायता समूह
- प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिभागी
- कॉलेज विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रैली सहकारिता के नारों से गूँजती रही—

“बिन सहकार नहीं उद्धार!”

“सहकारिता अमर रहे— भारत माता समृद्ध रहे!”

(शेष अगले पृष्ठ पर)

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आणंद के संकाय सदस्य एवं मध्यप्रदेश प्रभारी प्रो. प्रेम वासवानी का प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्धता हेतु मध्यप्रदेश प्रवास

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं संस्थानों की सम्बद्धता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आणंद (गुजरात) के संकाय सदस्य एवं मध्यप्रदेश प्रभारीप्रोफेसर प्रेम वासवानीद्वारा 13 एवं 17 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के प्रमुख सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तृत दौरा किया गया। इस प्रवास के दौरान जबलपुर और भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध संसाधन, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा संस्थागत गुणवत्ता सुधार हेतु महत्वपूर्ण चर्चाएँ आयोजित की गईं।

जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण

(पिछले पृष्ठ का शेष)

"सहकारिता से आत्मनिर्भर भारत"....

"एकता में शक्ति—सहकारिता में उन्नति!" मुख्यालय पहुँचकर रैली संपन्न हुई।

निबंध प्रतियोगिताएँ: युवाओं में सहकार चेतना का संचार

सहकारी सप्ताह के अंतर्गत दो स्तरों पर निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं—

कॉलेज स्तर

विषय : "सहकारिता : आत्मनिर्भर भारत का मंत्र"

भोपाल के कॉलेजों से आए विद्यार्थियों ने सहकारिता को रोजगार, उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताते हुए नवोन्मेषी विचार प्रस्तुत किए।

स्कूल स्तर

स्कूली बच्चों ने सहकारिता की सामाजिक महत्ता, सामूहिकता और राष्ट्रनिर्माण में इसकी भूमिका पर अपने सरल, सशक्त और प्रेरक विचार व्यक्त किए।

मुख्य संगोष्ठी : सहकारिता के विविध आयामों पर गहन विमर्श

"आत्मनिर्भर भारत के माध्यम के रूप में सहकारिता"

सह विषय—

"त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय: सहकारी अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा की भूमिका"

संगोष्ठी में उपस्थित रहे—

• मुख्य अतिथि:

श्री पी.एस. तिवारी, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, सहकारिता विभाग

• मुख्य वक्ता:

डॉ. सृष्टि उमेकर, डायरेक्टर, शरण फाउंडेशन

श्री पी.के.एस. परिहार, पूर्व महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक

श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ

श्री पी.एस. तिवारी – "सहकारिता : भारत की धड़कन"

अपने गहन भावपूर्ण उद्बोधन में उन्होंने कहा—

"भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ों में सहकारिता गहराई से निहित है। यह केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और अवसर देने की व्यवस्था है।"

उन्होंने बताया कि—

- सहकारिता लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है।
- छोटे उत्पादक और सीमांत किसान सामूहिकता से मजबूत बनते हैं।
- महिलाओं की सहभागिता सहकारी आंदोलन की आत्मा है।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि—

"सहकारिता को करियर, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के रूप में अपनाएँ। भविष्य उन्हीं का है जो सामूहिकता की शक्ति का उपयोग करना जानते हैं।"

डॉ. सृष्टि उमेकर – "माइक्रो से मैक्रो विकास का माध्यम सहकारिता"

उन्होंने अपने शोध-आधारित विचार प्रस्तुत करते हुए कहा—

"भारत में FPOs, SHGs, डेयरी और मत्स्य समितियाँ आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सहकारिता ने छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में बदलने की क्षमता सिद्ध की है।"

उन्होंने कहा—

- महिलाओं की सक्रिय भूमिका सहकारिता की सबसे बड़ी शक्ति है।
- SHGs ने लाखों परिवारों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाया है।
- सहकारिता में तकनीक और नवाचार का समावेश समय की आवश्यकता है।

उन्होंने सहकारी प्रशिक्षणों और नेतृत्व विकास पर विशेष बल दिया।

श्री पी.के.एस. परिहार – "सहकारी संस्थाओं की मजबूती के तीन स्तंभ"

श्री परिहार ने बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा—

"पारदर्शिता, सदस्य- केंद्रित शासन और सामूहिक निर्णय — यह तीन स्तंभ किसी भी सहकारी संस्था को मजबूत बनाते हैं।"

उन्होंने विशेष रूप से कहा—

- PACS के आधुनिकीकरण से ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा आएगी।
- डिजिटल रिकॉर्ड, ई-लेनदेन और तकनीकी निगरानी सहकारी संस्थाओं को विश्वसनीय बनाती है।
- संस्थाओं में युवा नेतृत्व को आगे लाना आवश्यक है।

श्री संजय कुमार सिंह – "आधुनिक प्रशिक्षण : सहकारिता की नई दिशा"

महाप्रबंधक श्री सिंह ने कहा— "सहकारी प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता-आधारित शिक्षण और शोधनिष्ठ प्रशिक्षण से सहकार क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।"

उन्होंने बताया—

- प्रशिक्षणों का विस्तार ग्रामीण स्तर तक किया जा रहा है।
- युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
- सहकारिता को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालना हमारी प्राथमिकता है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम : युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

श्री ऋतुराज रंजन ने बताया कि सहकारी संघ द्वारा एक विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है—

- छात्र वास्तविक सहकारी कार्य प्रणाली सीखेंगे।
- प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- यह कार्यक्रम युवाओं को कौशल, अनुभव और रोजगार से जोड़ने का सेतु बनेगा।

मुख्य अतिथियों द्वारा—

- दीप प्रज्वलन
- माँ सरस्वती का पूजन किया गया।

प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत, तथा प्रतिभागियों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम का संचालन—श्री संतोष येडे, सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्टद्वारा किया गया।

आभार व्यक्त किया—

महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, स्टाफ और विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हुए आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।

केंद्र का निरीक्षण (13 नवम्बर 2025)

दिनांक13 नवम्बर 2025 को प्रो. वासवानी ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर का निरीक्षण करते हुए वहाँ के अधोसंरचना विकास, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, हॉस्टल, पुस्तकालय तथा स्मार्ट क्लास सुविधा का अवलोकन किया।

- केंद्र के प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के साथ विस्तृत बैठक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षुओं की उपलब्धियों तथा सहकारिता क्षेत्र में मानव संसाधन निर्माण पर चर्चा हुई।
- सहकारी संस्थाओं की नई नीतियों, डिजिटल प्रबंधन प्रणाली, ई-लर्निंग मॉड्यूल तथा सहकारी विश्वविद्यालय से भविष्य की सम्बद्धता की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

जबलपुर में भ्रमण कार्यक्रम

प्रशिक्षण केंद्र के निरीक्षण के पश्चात प्रो. वासवानी को जबलपुर स्थित प्रमुख सहकारी एवं उत्पादक संस्थानों का भ्रमण कराया गया, जिसमें—

- सांची दुग्ध संघ, जबलपुर का विस्तृत निरीक्षण शामिल रहा, जहाँ दुग्ध संग्रहण, प्रोसेसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं आपूर्ति प्रणाली की जानकारी दी गई।
- गांधी शिल्प बाजारका दौरा कर स्थानीय हस्तशिल्पियों, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

भोपाल सहकारी प्रशिक्षण केंद्र एवं मुख्यालय का भ्रमण (17 नवम्बर 2025)

दिनांक17 नवम्बर 2025 को प्रो. वासवानी ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल का निरीक्षण किया।

- प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पद्धति, पाठ्य सामग्री, कम्प्यूटर लैब, पोर्टल तथा ग्रामीण सहकारिता पर आधारित विशेष प्रशिक्षणों की जानकारी प्रस्तुत की गई।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता उन्नयन, तकनीकी नवाचार, फील्ड मॉनिटरिंग तथा सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की।

मुख्यालय का औपचारिक अवलोकन

इसके बाद प्रो. वासवानी ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, मुख्यालय भोपाल का भ्रमण किया, जहाँ—

- संघ के प्रबंध संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजनाओं, प्रकाशन, शोध कार्यों तथा सहकारी संस्थाओं की क्षमता निर्माण गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया।
- सहकारी विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ।
- प्रशिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ीकरण, मूल्यांकन तथा मान्यता संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

NIRDPR, हैदराबाद में "वित्तीय समावेशन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका" विषयक 5-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), राजेंद्र नगर, हैदराबाद में आयोजित 5-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका" का अंतिम दिवस गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों द्वारा अपनी-अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, फीडबैक साझा किया गया तथा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया।

समापन सत्र में प्रशिक्षार्थियों ने कार्यक्रम निदेशक श्री ए. देबप्रिया तथा सह-निदेशक डॉ. डी. रविका पुष्प-गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। दोनों गणमान्य अधिकारियों ने प्रशिक्षार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए सहकारी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर पुनः प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को अपने-अपने राज्यों में सीखी गई तकनीकों को लागू करने हेतु प्रेरित किया।

प्रशिक्षण के संदर्भ में सभी प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि—

"NIRDPR में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने हमें आधुनिक वित्तीय प्रक्रियाओं, सहकारी संस्थाओं की संरचना, सामुदायिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार तथा समावेशी वित्त मॉडल्स को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान, मार्गदर्शन एवं व्यावहारिक अभ्यास हमारे व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास हेतु अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे।"

प्रतिभागियों ने विशेष रूप से बताया कि कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाने की प्रशिक्षकों की शैली, प्रत्येक प्रश्न का धैर्यपूर्वक समाधानतथा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण—इन सभी ने कार्यक्रम को अत्यंत सफल एवं प्रभावी बनाया।प्रशिक्षण न केवल कौशल-विकास का माध्यम रहा, बल्कि इसने प्रतिभागियों में समुदाय की बेहतर सेवा करने का उत्साह भी उत्पन्न किया।

समापन अवसर पर प्रशिक्षकश्री पीयूष रॉयने सभी प्रशिक्षार्थियों की ओर से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि—

"यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सभी के लिए सीखने, अनुभव साझा करने और सहकारी क्षेत्र में नवाचारों को समझने का उत्कृष्ट मंच साबित हुआ है। हम NIRDPR के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना उपयोगी और प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया।"आभार ज्ञापन के उपरांत कार्यक्रम का औपचारिक समापन किया गया। सभी प्रतिभागी प्रेरणा और नए संकल्प के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के लिए रवाना हुए।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 : डबरा में भव्य सम्मेलन

उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाएँ सम्मानित सहकारिता आंदोलन को गति देने का संकल्प, बड़ी संख्या में सदस्य शामिल

डबरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर डबरा में जिला सहकारी संघ ग्वालियर के तत्वावधान में सहकारी समितियों का भव्य सम्मेलन ऐतिहासिक उत्साह और गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियरश्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्षश्री के. डी. सिंह (वरिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी) और विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकार भारती के प्रदेश मंत्रीअजय मिश्रातथा जिला महामंत्रीअरुण कुमार शर्माउपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारिता आज स्वावलंबन और सामुदायिक विकास का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि देश की लगभग 45% आबादीप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता से जुड़ी है, जो इस आंदोलन की व्यापकता और उपयोगिता को दर्शाता है।सहकार भारती के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय गठन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को नई ऊर्जा, पारदर्शिता और विस्तार मिला है।अध्यक्षता कर रहे श्री के. डी. सिंह ने मत्स्य तथा दुग्ध क्षेत्र की सहकारी समितियों को और बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता तभी मजबूत होगी जब सदस्य संतुष्ट, जागरूक और सशक्त होंगे।

इंदौर, नौगाँव (छतरपुर) व जबलपुर में 72वें सहकारी सप्ताह का आयोजन, सहकारिता ध्वज फहराकर मनाया दिवस

भोपाल। 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों- इंदौर, नौगाँव जिला छतरपुर तथा जबलपुर - में सहकारिता का संदेश जन-जन तक पहुँचाने हेतु विविध कार्यक्रमों का गरिमामय आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारिता ध्वज का ध्वजारोहणकिया गया। "सहकारिता गीत" का सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से उत्साहपूर्वक गायन किया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर: ध्वजारोहण के बाद प्राचार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सहकारिता के ऐतिहासिक महत्व तथा प्रदेश में सहकारी संगठन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। कर्मचारीगण ने "सहकारिता से आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को दोहराया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगाँव, जिला छतरपुर: नौगाँव केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों और स्थानीय सहकारी संगठनों के

प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि सहकारी संस्थाएँ किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बना रही हैं।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर: जबलपुर केन्द्र पर ध्वज फहराने के उपरांत कर्मचारियों ने सहकारी मूल्यों के प्रचार-प्रसार हेतु "जन-जागरण" और "कौशल उन्नयन प्रशिक्षण" को अधिक व्यापक बनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश में सहकारी मानव संसाधन तैयार करने का महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

तीनों केन्द्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए नवाचारों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा—ताकि यह प्रणाली अधिक पारदर्शी, सहभागी और आत्मनिर्भर बने।कार्यक्रम के अंत में सभी ने सहकारिता सप्ताह के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाने तथा सहकारी संस्थाओं को विकास आधारित, सेवा उन्मुख और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सतत प्रयास करने की प्रतिज्ञा ली।

नया व्यापार सृजित करने वाले कर्मचारी को इंसेंटिव देने की योजना जल्द : मंत्री श्री सारंग

● 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापन समारोह ● डिफॉल्टर किसानों के लिये भी योजना होगी शुरू
● अपेक्स बैंक में ई-ऑफिस और सहकार-सेतु पोर्टल का शुभारंभ

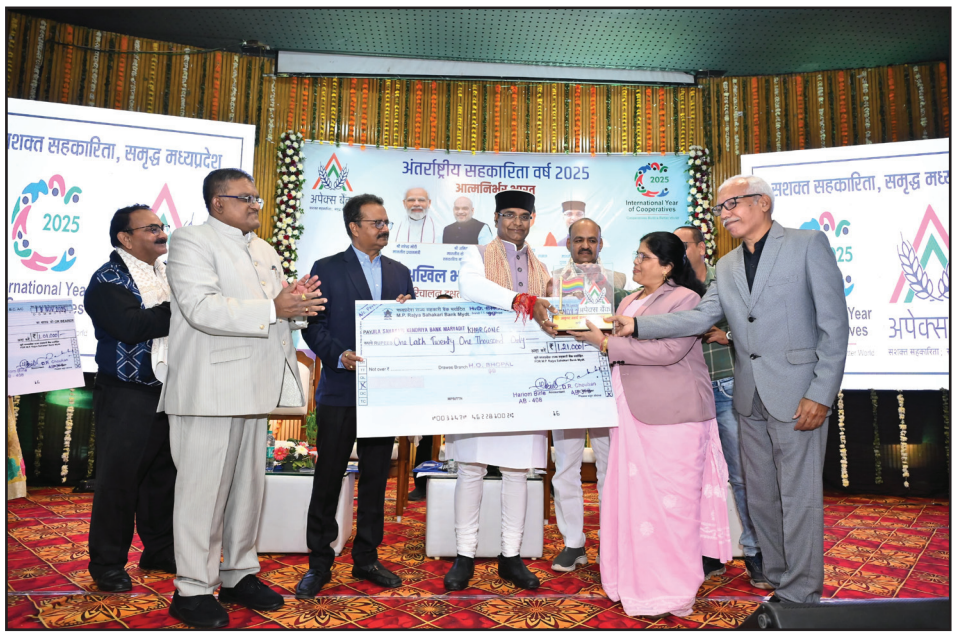

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि पैक्स में नया व्यापार सृजित करने वाले कर्मचारी को इंसेंटिव देने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही डिफॉल्टर किसानों के लिये भी योजना लाई जा रही है। इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि सोसायटी में कुछ गडबड़ी पर भी किसानों पर असर नहीं हो। यह बात मंत्री श्री सारंग ने अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आयोजित 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह में कही। समारोह में 'परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने' विषयक पर चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी बैंकों और पैक्स को सम्मानित किया। उन्होंने अपेक्स बैंक में ई-ऑफिस तथा सहकार-सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया।

कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी आंदोलन के हर आयाम को मजबूती के साथ स्थापित कर रही है। कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का काम कर रही है। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के माध्यम से सहकारी आंदोलन मजबूत होगा और सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी के माध्यम से हर पैक्स को कॉरपोरेट के साथ जोड़कर नये आयाम स्थापित किये जा रहे है। इससे पैक्स के साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। पैक्स को फायदे के साथ कर्मचारी को भी लाभ दिलवाने का काम किया जायेगा।

सहकारिता विभाग की प्रत्येक पहल प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिये

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन तथा केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि मिशन से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश का सहकारिता विभाग सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लेकर सीपीपीपी तक सहकारिता विभाग की प्रत्येक पहल प्रदेश के किसानों की खुशहाली तथा ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सहकारिता को जमीनी स्तर पर पहुँचना ही उद्देश्य

सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प ने कहा कि यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। अब यह अंतिम पडाव पर है। इसका उद्देश्य सहकारिता को जमीनी स्तर पर पहुँचना है। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरूण माथुर सहित मध्यप्रदेश की सभी प्रादेशिक सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समापन समारोह में मध्यप्रदेश में सहकारिता के विकास पर और अपेक्स बैंक बैकिंग नेटवर्क पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। शुरूआत में परिसर में सहकारी झंडा रोहण और सहकारी गान हुआ।

सम्मान एवं पुरस्कार

समारोह में प्रदेश के 3 उत्तम जिला बैंकों पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार जिला बैंक विदिशा को एक लाख 51 हजार का चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह ने प्राप्त किया। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार जिला बैंक खरगोन को एक लाख 25 हजार का चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती संध्या रोकडे तथा तृतीय पुरस्कार जिला बैंक रतलाम को एक लाख एक हजार रूपये का चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक कुमार जैन ने प्राप्त किया। पैक्स का शत प्रतिशत अंकेक्षण पूर्ण करने वाले प्रथम 3 जिलों में खरगोन, मंडला और सीहोर को एक-एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। ई-पैक्स को सफल क्रियान्वयन करने वाली पैक्स सिरलाय (खरगोन), मनेरी (बालाघाट) और गोविंदपुर (सतना) को भी सम्मानित किया गया। समारोह में बेंचमार्किंग के आधार प्रथम 3 नागरिक सहकारी बैंक मंदसौर, उज्जैन और इंदौर को भी पुरस्कृत किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।